बृहस्पतिवार, 19 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

आईसीसी टी20 रैंकिंग में ईशान किशन की बड़ी छलांग,

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

युवराज सिंह की बायोपिक में निभाना चाहते हैं

Page-05

रूस का विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से ऊर्जा खरीद को लेकर भारत पर अप्रत्यक्ष सवाल उठाए थे।यूक्रेन संकट के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल आयात बढ़ाया है।मॉस्को का कहना है कि भारत-रूस ऊर्जा सहयोग वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति संतुलन और मूल्य स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।

भारत-रूस ऊर्जा साझेदारी से वैश्विक बाजार को मजबूती

अंतर्राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

रूस का विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के हालिया दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र में जारी सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए लाभकारी है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत-रूस ऊर्जा साझेदारी पूरी तरह से पारस्परिक हितों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना है।मंत्रालय के बयान में कहा गया कि कुछ पश्चिमी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। रूस का कहना है कि भारत के साथ उसका ऊर्जा सहयोग अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और इसमें किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि शामिल नहीं है। बयान में यह भी जोड़ा गया कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही भू-राजनीतिक तनावों के कारण दबाव में है, ऐसे में स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।भारत और रूस के बीच तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रूस, भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक अनुबंधों और रियायती दरों पर तेल आपूर्ति की व्यवस्था ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती दी है, वहीं रूस को भी अपने ऊर्जा निर्यात के लिए एक बड़ा और स्थिर बाजार मिला है।रूस के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे

अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ऊर्जा को राजनीतिक दबाव का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग, संवाद और संतुलित नीतियों की आवश्यकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-रूस ऊर्जा सहयोग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति का संतुलन बना रहता है, जिससे तेल की कीमतों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यह साझेदारी एशियाई और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

एआई समिट में भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत ने "24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने" का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। 16-17 फरवरी के दौरान 24 घंटों में कुल 2,50,946 वैध प्रतिज्ञाएं प्राप्त हुईं यह ऐतिहासिक उपलब्धि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान घोषित की गई। इस अवसर पर MeitY के सचिव एस कृष्णन, अतिरिक्त सचिव, इंडियाएआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह, इंडियाएआई की सीओओ कविता भाटिया, इंटेल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवासन अयंगर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक प्रवीण पटेल उपस्थित थे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ने युवाओं को एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया। 2,50,000 छात्रों ने भाग लिया, जो देश के लिए गर्व का दिन है। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत को ऐसे भविष्य की ओर ले जाएगी, जहां एआई को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ अपनाया जाएगा।

ममता बोली- ED केंद्र का हथियार

ममता सरकार और ED आमने-सामने, सुप्रीम कोर्ट में बहस

पश्चिम बंगाल, टीवी भारतवर्ष

पश्चिम बंगाल में I-PAC से जुड़े रेड मामले की सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) का विपक्षी शासित राज्यों में राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।केंद्रीय एजेंसी ने पलटवार करते हुए कहा कि वह किसी का हथियार नहीं है और बंगाल में उन्हें मुख्यमंत्री और पुलिस द्वारा धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय किया जाएगा कि किसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया गया और किसे धमकाया गया।ED ने I-PAC रेड मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। ED का आरोप है कि 8 जनवरी को I-PAC कार्यालयों पर रेड के दौरान कार्रवाई में ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस ने बाधा डाली।सर्च ऑपरेशन के दौरान मुख्यमंत्री और TMC नेता I-

PAC कार्यालय पहुंचे और काफी हंगामा हुआ। ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसी पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया और कई फाइलें बाहर निकालीं।TMC का कहना है कि I-PAC चुनाव रणनीतिकार है और ED ने गोपनीय चुनाव रणनीति से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल पुलिस ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 मार्च तक स्थगित कर दी है।

राज्यसभा चुनाव 16 मार्च:

विपक्ष के 25 और NDA के 12 सीटों पर मुकाबला

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। खाली हो रही 37 सीटों में एनडीए के पास 12 और विपक्ष के पास 25 सीटें हैं।सबसे अधिक चुनाव महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, और पश्चिम बंगाल व बिहार की 5-5 सीटों पर होंगे। इनमें शरद पवार, रामदास अठावले, कणिमोझी, तिरुचि शिवा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।चुनाव आयोग ने मतदान के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित वॉयलेट रंग के स्केच पेन के ही उपयोग की चेतावनी दी है। किसी अन्य पेन से डाला गया वोट मान्य नहीं होगा।आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक

नियुक्त किए हैं। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में EVM और VVPAT जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 1.20 लाख से अधिक लोगों ने डेमो कैंप में हिस्सा लिया और 1.16 लाख से अधिक ने मॉक वोट डाले। 29 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन मोबाइल डेमो वैन से कवर किए जा चुके हैं।

भारत-यूके अपतटीय पवन सहयोग से हरित ऊर्जा को नई दिशा

भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता 272 GW पार

अंतर्राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता और स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में घोषणा की कि भारत की गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता अब 272 गीगावाट (GW) से अधिक हो गई है। यह ऐतिहासिक घोषणा 'भारत-ब्रिटेन अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल' (India-UK Offshore Wind Working Group) की शुरुआत के मौके पर की गई, जिसमें ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून भी उपस्थित थे।इस अवसर पर मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 35 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा और 4.61 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया, जो निर्धारित लक्ष्य से लगभग पांच वर्ष पहले पूरा हो गया।जोशी ने विस्तार से बताया कि वर्तमान में भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता 272 गीगावाट से अधिक है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 141 गीगावाट और पवन ऊर्जा का 55 गीगावाट है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दो साल से कम समय में लगभग 30 लाख परिवारों को रूफटॉप सोलर की सुविधा मिली है। इसी तरह, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत 21 लाख पंप सौर ऊर्जा से संचालित

किए गए हैं।मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि स्पष्ट नीति, संस्थागत समन्वय और निवेशकों एवं उद्योग के भरोसे का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि अगले चरण में विश्वसनीयता, ग्रिड स्थिरता, औद्योगिक गहराई और ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना आवश्यक होगा।अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाएँ भी स्पष्ट की गईं। जोशी ने बताया कि गुजरात और तमिलनाडु के तटों के पास अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक 10 गीगावाट क्षमता (प्रत्येक राज्य में 5-5 गीगावाट) की पारेषण योजना पूरी कर ली गई है। प्रारंभिक परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए 7,453 करोड़ रुपये (लगभग 71 करोड़ पाउंड) की व्यवहार्यता अंतर निधि योजना शुरू की गई है।मंत्री ने कहा, "अपतटीय पवन ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का सबसे जटिल क्षेत्र है। इसके लिए विशेष बंदरगाह ढांचा, समुद्री लॉजिस्टिक, समुद्र तल पट्टे की व्यवस्था और व्यवहार्य व्यावसायिक ढांचे की आवश्यकता होती है।" इसी को ध्यान में रखते हुए भारत-ब्रिटेन कार्यबल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र को रणनीतिक दिशा और समन्वय देना है।जोशी ने तीन मुख्य स्तंभों पर कार्य की रूपरेखा बताई: पहला, पारिस्थितिकी योजना और बाजार संरचना; दूसरा, ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें बंदरगाह आधुनिकीकरण, स्थानीय निर्माण और कौशल विकास शामिल है; तीसरा, वित्तपोषण और जोखिम न्यूनीकरण, जिसमें मिश्रित वित्तीय ढांचे और दीर्घकालिक पूंजी का उपयोग शामिल है। उन्होंने कहा कि अपतटीय पवन को पारेषण योजना, भंडारण समाधान और उभरते तटीय हरित हाइड्रोजन समूहों से भी जोड़ना होगा।मंत्री ने अंत में कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन की कीमत घटकर सबसे कम 279 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। यह कार्यबल भारत और ब्रिटेन के बीच विश्वास और सहयोग का प्रतीक है, जो वास्तविक चुनौतियों के समाधान में मदद करेगा।

रुपया मजबूत होकर 90.67 पर खुला

कच्चे तेल की गिरावट और एफआईआई निवेश से मिला समर्थन

बुधवार को रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 90.67 प्रति डॉलर पर पहुंचा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और एफआईआई की खरीदारी से उसे समर्थन मिला। हालांकि डॉलर की मजबूती और शेयर बाजार में गिरावट ने बढ़त सीमित कर दी। ब्रेंट क्रूड 68.40 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

बुधवार को विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच पैसे की बढ़त के साथ 90.67 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में लगातार निवेश बनाए रखने से रुपये को शुरुआती समर्थन मिला। हालांकि, अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट ने रुपये की तेजी को सीमित कर दिया।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.60 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला और यह 90.67 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव की तुलना में पांच पैसे की मजबूती को दर्शाता है। मंगलवार को रुपया दो पैसे की बढ़त के साथ 90.72 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से आयात बिल पर दबाव कम होने की उम्मीद रहती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव रुपये पर पड़ता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में कच्चे तेल के दाम में गिरावट घरेलू मुद्रा के लिए राहतकारी मानी जाती है।इस बीच, छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.10 प्रतिशत बढ़कर 97.24 पर पहुंच गया। डॉलर में आई यह मजबूती उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बनाती है, जिससे रुपये की बढ़त सीमित हो गई।घरेलू शेयर बाजारों में भी शुरुआती कारोबार के दौरान कमजोरी का रुख देखा गया। सेंसेक्स 77.56 अंक की गिरावट के साथ 83,373.40 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 26.25 अंक फिसलकर 25,699.15 अंक पर आ गया। विश्लेषकों का मानना है कि शेयर बाजार में गिरावट से विदेशी निवेशकों की धारणा प्रभावित हो सकती है, जिसका असर मुद्रा बाजार पर भी पड़ता है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.36 प्रतिशत गिरकर 68.40 डॉलर प्रति बैरल रह गया। ऊर्जा कीमतों में यह नरमी भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जाती है। कम तेल कीमतें न केवल चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, बल्कि महंगाई पर भी दबाव कम करती हैं, जिससे मुद्रा को समर्थन मिलता है।शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक मंगलवार को लिवाल रहे। उन्होंने शुद्ध रूप से 995.21 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। एफआईआई की यह खरीदारी बाजार में तरलता बढ़ाती है और विदेशी मुद्रा प्रवाह को समर्थन देती है, जिससे रुपये को मजबूती मिलती है।विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में रुपये की दिशा वैश्विक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेश प्रवाह पर निर्भर करेगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, डॉलर सूचकांक की चाल और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक घटनाक्रम भी रुपये की चाल को प्रभावित कर सकते हैं।फिलहाल, शुरुआती कारोबार में रुपये की मजबूती यह संकेत देती है कि वैश्विक और घरेलू कारकों का संतुलित प्रभाव बना हुआ है। हालांकि, बाजार में जारी अस्थिरता को देखते हुए निवेशकों और आयात-निर्यात से जुड़े कारोबारियों की नजर प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर बनी रहेगी। कुल मिलाकर, कच्चे तेल में नरमी और विदेशी निवेश के समर्थन से रुपये ने सकारात्मक शुरुआत की, लेकिन डॉलर की मजबूती और घरेलू बाजार की कमजोरी ने इसकी बढ़त को सीमित कर दिया।

बीएनपी के शपथ लेने के बाद जमात-एनसीपी ने कैबिनेट बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां सत्ता में आई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और दूसरी बड़ी पार्टी जमात इस्लामी के बीच मतभेद सामने आए हैं। 12 फरवरी को हुए चुनाव में बीएनपी ने 212 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, जबकि जमात और उसकी गठबंधन सहयोगी नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) समेत 11 दलों ने मिलकर 77 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव के साथ-साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी कराया गया, जिसे 62% लोगों ने समर्थन दिया। तारिक रहमान की पार्टी सत्ता में आते ही राजनीतिक विवादों में घिर गई। बीएनपी के निर्वाचित सांसदों ने सांसद के रूप में तो शपथ ले ली, लेकिन जुलाई चार्टर से जुड़े संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने से इंकार कर दिया। इस कदम से नाराज जमात और एनसीपी ने कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। जुलाई चार्टर का उद्देश्य संसद को 180 दिनों के लिए संविधान सभा में बदलना है, जिससे नई संसद बांग्लादेश के संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में आवश्यक बदलाव कर सके। बीएनपी ने चार्टर पर अनिच्छा के साथ हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसके नेताओं का कहना है कि चार्टर के कई प्रावधानों पर पार्टी को आपत्ति थी और तैयार करते समय उनसे राय नहीं ली गई। मंगलवार को शपथ ग्रहण के दौरान बीएनपी के सांसद संविधान सुधार आयोग के लिए शपथ नहीं लिए, जबकि जमात-एनसीपी के निर्वाचित सांसदों ने दोनों शपथ ली। तारिक रहमान ने इसी दिन शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही जमात और एनसीपी ने बीएनपी को फांसीवादी ताकत बताते हुए सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई चार्टर को लेकर मौजूदा गतिरोध बांग्लादेश में राजनीतिक आंदोलन और अस्थिरता को बढ़ा सकता है, जिससे पिछले वर्षों में देखे गए विरोध प्रदर्शन दोबारा सक्रिय हो सकते हैं।

दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सुंदर पिचाई

एआई समिट और तकनीक पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा

जनवरी 2026 में रूस से भारत का आयात 40% गिरा

कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की रणनीति तेज़

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

जनवरी 2026 में रूस से भारत के आयात में तेज गिरावट दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और नए ट्रेड डेटा के अनुसार, पिछले साल इसी महीने के मुकाबले रूस से आयात लगभग 40 प्रतिशत कम होकर $4.81 बिलियन से घटकर $2.86 बिलियन हो गया। इस गिरावट का मुख्य कारण भारतीय रिफाइनरी कंपनियों द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में भारी कटौती है। रूस से भारत का अधिकांश आयात—लगभग 80 प्रतिशत—कच्चे तेल का होता है। अनुमान है कि जनवरी में रूस से भेजे गए तेल शिपमेंट की कीमत लगभग $2.3 बिलियन या उससे कम रही।रूस से क्रूड ऑयल की खरीद में कमी अचानक नहीं हुई। यह तब शुरू हुई जब पिछले साल अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी और ट्रेड प्रेशर डालते हुए रूस से तेल आयात घटाने का दबाव बनाया। इस दौरान भारतीय आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, जिससे रिफाइनर कंपनियों ने रूस से क्रूड खरीद कम कर दी। उदाहरण के लिए, भारत की प्रमुख प्राइवेट रिफाइनर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जनवरी में रूस से कोई डिलीवरी की उम्मीद नहीं जताई। अन्य रिफाइनर कंपनियों ने भी बढ़ी लागत और पेनल्टी से बचने के लिए आयात घटा दिया।विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में रूस से आयात में यह कमी जारी रह सकती है। भारतीय रिफाइनर अब वेनेजुएला, अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे देशों से सस्ते तेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह कदम रूसी क्रूड पर निर्भरता कम करने और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड दबावों का सामना करने की रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में अमेरिकी पेनल्टी कम होने से भारत की ट्रेड पोजीशन और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को फायदा मिलने की उम्मीद है।

जिनेवा परमाणु वार्ता बेनतीजा,

पश्चिम एशिया में बढ़ा सैन्य तनाव

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

दुनिया एक बार फिर अत्यंत नाजुक दौर से गुजरती नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई अहम वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। लगभग तीन घंटे तक चली इस बैठक से उम्मीद की जा रही थी कि परमाणु मुद्दे पर कोई ठोस समाधान या आगे की रूपरेखा सामने आएगी, लेकिन बातचीत के बाद स्थिति पहले से अधिक अनिश्चित दिखाई दे रही है।सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के बीच यह परोक्ष वार्ता का दूसरा दौर था, जो भी बेनतीजा रहा। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन किसी ठोस सहमति तक पहुंचा नहीं जा सका। यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब पश्चिम एशिया पहले ही गहरे तनाव से गुजर रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।इसी बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है। अमेरिकी कदम को लेकर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। ईरान का कहना है कि क्षेत्र में बाहरी सैन्य गतिविधियां हालात को और जटिल बना रही हैं।तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान ने होरमूज़ जलडमरूमध्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मिसाइल परीक्षण किए। सरकारी एजेंसी के अनुसार, मिसाइलें ईरानी तट और विभिन्न ठिकानों से दागी गईं और सभी ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा। ईरान ने दावा किया कि यह अभ्यास पूरी तरह सफल रहा और उसकी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन है।विशेषज्ञों का मानना है कि होरमूज़ जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक अहम मार्ग है, ऐसे में वहां किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि से अंतरराष्ट्रीय बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है। ईरान द्वारा इस संवेदनशील क्षेत्र में मिसाइल अभ्यास शुरू किए जाने से तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम को लेकर मतभेद बने हुए हैं। जिनेवा में हुई हालिया वार्ता से उम्मीद थी कि दोनों पक्ष किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बातचीत के निष्कर्षहीन रहने से कूटनीतिक प्रयासों को झटका लगा है। मौजूदा हालात में दोनों देशों के रुख को देखते हुए क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

रावी नदी का अतिरिक्त पानी भारत में रहेगा,

पाकिस्तान को रणनीतिक झटका

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

सिंधु जल संधि के निलंबन की चर्चाओं के बीच भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा रणनीतिक झटका देने की तैयारी पूरी कर ली है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सीमा पर स्थित शाहपुर कंडी डैम का निर्माण कार्य अब पूर्णता की ओर है, और इसके पूरा होने के बाद रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की बजाय पूरी तरह भारत में ही रुक जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के मंत्री Javed Ahmed Rana ने इस परियोजना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि डैम के बनने के बाद पाकिस्तान जाने वाला पानी कठुआ और सांबा जिलों की ओर मोड़ दिया जाएगा, जो लंबे समय से सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं। शाहपुर कंडी डैम परियोजना की कल्पना लगभग पांच दशक पहले 1979 में रावी नदी के बहाव को नियंत्रित करने और पंजाब व जम्मू-कश्मीर में सिंचाई के लिए की गई थी। इसका शिलान्यास 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री Indira Gandhi ने किया था। हालांकि, पंजाब और जम्मू-कश्मीर सरकारों के बीच प्रशासनिक और तकनीकी दिक्कतों के कारण डैम के निर्माण में लंबा समय लगा। 2008 में

इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला, और अब 2,715.70 करोड़ रुपये के निवेश से इसे अंतिम चरण में पहुंचाया गया है। यह परियोजना पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है, रंजीत सागर डैम से 11 किमी नीचे और माधोपुर हेडवर्क्स से 8 किमी ऊपर। डैम सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह माधोपुर हेडवर्क्स से निकलने वाले कैनाल सिस्टम को समान पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे पंजाब में लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई संभव हो सकेगी और जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब दोनों में खेती के लिए नियमित पानी उपलब्ध होगा।सिंचाई के अलावा, शाहपुर कंडी डैम से हर साल 1,042 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना पाकिस्तान को जाने वाले पानी की मात्रा कम करेगी और इस सीमा क्षेत्र में पर्यटन के नए अवसर पैदा करेगी। इसके साथ ही यह क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करने में मदद करेगा।

संपादक की कलम से

वैश्विक ऊर्जा बाजार इन दिनों अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति बाधाओं के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और रूस के बीच बढ़ती ऊर्जा साझेदारी को केवल द्विपक्षीय व्यापार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक बाजार की स्थिरता के व्यापक संदर्भ में समझना आवश्यक है। हाल ही में रूस का विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत-रूस ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के हित में होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है।यूक्रेन संकट के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया। इस दौरान भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रियायती दरों पर रूसी तेल आयात बढ़ाया। यह निर्णय व्यावहारिक और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप था। एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थिर और किफायती ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है, ताकि विकास की गति बनी रहे और घरेलू महंगाई नियंत्रित रहे।दूसरी ओर, रूस के लिए भारत एक विशाल और विश्वसनीय बाजार के रूप में उभरा है। इससे रूस को अपने ऊर्जा निर्यात के लिए वैकल्पिक मार्ग मिला, वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अचानक आई कमी को भी आंशिक रूप से संतुलित किया जा सका। ऊर्जा व्यापार का यह प्रवाह अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता बनाए रखने में सहायक रहा है, जिससे कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को सीमित करने में मदद मिली।हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने इस सहयोग पर आपत्ति जताई है, परंतु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को राजनीतिक दबाव का उपकरण बनाना दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। प्रत्येक देश को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक हितों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। वैश्विक बाजार की वास्तविक स्थिरता प्रतिस्पर्धा, विविधीकरण और सहयोग से ही संभव है, न कि प्रतिबंधों और दबाव की राजनीति से।

असम में कांग्रेस में उथल-पुथल:

भूपेन कुमार बोराह का इस्तीफा, भाजपा में शामिल होने की संभावना

असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जब पूर्व APCC अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपमान और गठबंधन विवाद को कारण बताया। बोराह के भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे असम की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

असम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को एक बार फिर से राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी (APCC) अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह ने सोमवार को पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, जिससे राज्य में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। उनकी घोषणा के तुरंत बाद कुछ स्थानीय पार्टी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की और अपने फैसले पर पुनर्विचार किया था। हालांकि, हालिया घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि बोराह ने कांग्रेस से संबंध तोड़ लिया है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने की संभावना है।भूपेन कुमार बोराह ने इस्तीफे के पीछे कई राजनीतिक और व्यक्तिगत कारण बताए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने 32 साल समर्पित किए, लेकिन कई मौकों पर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। बोराह ने कहा, "मैंने राहुल गांधी को भी इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कांग्रेस को विधायक से लेकर APCC अध्यक्ष तक का पद संभाला, गठबंधन बनाए और पार्टी के लिए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।"उन्होंने आगे कहा कि जब वे 2021 में अध्यक्ष बने, तब कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन में थी, जिसे उन्होंने अपने प्रयासों से तोड़ दिया। इसके बाद इंडिया गठबंधन बनने से पहले उन्होंने 16 पार्टियों के साथ गठबंधन तैयार किया। बोराह ने बताया कि उपचुनाव में तय हुआ था कि एक सीट सीपीआई (एमएल) को मिलेगी, लेकिन अचानक उसी रात किसी ऐसे व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया गया, जिसने कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं रहा। इसके परिणामस्वरूप गौरव गोगोई वह सीट नहीं जीत सके। भूपेन बोराह ने कहा कि 9 फरवरी को गठबंधन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनसे फिर से गठबंधन बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने बातचीत शुरू की, लेकिन 11 फरवरी को गौरव गोगोई ने कहा, "आप अकेले मत जाइए, रकीबुल हुसैन को भी साथ ले जाइए।" इसके बावजूद, 13 फरवरी को गौरव गोगोई ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि भूपेन बोराह ने गलतफहमी पैदा की है। बोराह ने इस अपमान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से भी इस पर चर्चा की, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि बोराह भाजपा में शामिल होने के बहाने ऐसा कर रहे थे। उन्होंने कहा, "जब कोई भाजपा में शामिल होता है, उसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वह उसी के अनुसार बोले। असम के लोग सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस में ही समस्याएँ थीं, तो आप भाजपा विरोधी अन्य पार्टियों में क्यों नहीं गए? आपने इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही हिमंता बिस्वा सरमा से हाथ क्यों मिलाया?"विशेषज्ञों का मानना है कि भूपेन कुमार बोराह का इस्तीफा असम में कांग्रेस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह कदम पार्टी की छवि और संगठनात्मक मजबूती पर प्रश्नचिह्न लगाता है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बोराह का भाजपा की ओर रुख करना राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है और कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति में चुनौती पैदा कर सकता है। भूपेन बोराह की रणनीति और उनकी बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं को देखते हुए असम में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष बढ़ता दिख रहा है, जबकि BJP इस अवसर का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तैयार है। आगामी महीनों में असम की राजनीति में इस विवाद के परिणाम और उसकी गूंज राज्य की चुनावी परिदृश्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकती है।

हम बार-बार झुकने वाले नहीं: CM एम.के. स्टालिन ने केंद्र को दी चेतावनी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्तता देने और संविधान में संशोधन करने की मांग दोहराई। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों की शक्तियों को कम करने और सारी निर्णय क्षमता अपने हाथ में रखने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को ऐसी स्थिति में धकेल दिया गया है, जहां उसे अपने हक के फंड और संसाधन पाने के लिए केंद्र से लगातार संघर्ष करना पड़ता है।मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, "हम अभी भी हर फंड और अधिकार के लिए केंद्र सरकार से लड़ते हैं। कब तक हम ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां वे देते हैं और हम केवल लेते हैं?" उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का पहला भाग विधानसभा में पेश कर दिया गया है।स्टालिन ने जोर देकर कहा कि संविधान में संशोधन करके सभी राज्यों को पूर्ण रूप से सशक्त और स्वायत्त सरकारों में बदलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भूमि और वित्तीय शक्तियों पर अधिकार सुनिश्चित करना राज्यों का मौलिक हक है और इसके लिए संघर्ष करना अपरिहार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संघवाद ही आधारशिला है, और राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित किए बिना सुशासन संभव नहीं है।उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मांग किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि राजनीतिक मतभेदों से परे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने कहा, "केंद्र सरकार, जिसने सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रीकृत कर रखी हैं, राज्य सरकारों का सम्मान नहीं करती। हम बार-बार झुकने वाले लोग नहीं हैं। हमें राज्य स्वायत्तता और केंद्र में मजबूत संघवाद चाहिए। तभी हम सुशासन बहाल कर सकते हैं।

कांग्रेस ने खारिज किए कपिल सिब्बल के एपस्टीन फाइल्स से जुड़े आरोप,

भाजपा पर झूठा नैरेटिव बनाने का लगाया आरोप

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के नाम को जेफ्री एपस्टीन फाइल्स से जोड़ने वाले दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। खेड़ा ने कहा कि भाजपा नेता इस मामले में झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बिना पूरी जानकारी के विपक्षी नेताओं को विवाद में खींचने का प्रयास कर रहे हैं।खेड़ा ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट में बताया कि जिस दस्तावेज का हवाला दिया जा रहा है, वह 59 पन्नों का एक कैलेंडर है। इसमें न्यूयॉर्क में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों, कॉन्फ्रेंस और फंडरेजर की लिस्ट शामिल है। यह दस्तावेज कथित तौर पर 10 सितंबर 2010 को मार्गोक्स रोजर्स ने एपस्टीन की निजी सहायक लेस्ली ग्रॉफ को भेजा था।उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल का नाम लिस्ट के पेज 55 पर एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने उन्हें वैश्विक शिक्षा सहयोग में योगदान के लिए सम्मानित किया था। इस सम्मान समारोह का एपस्टीन से कोई संबंध नहीं था, और सिब्बल के एपस्टीन के साथ किसी बैठक या निजी संपर्क का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया था कि एपस्टीन से जुड़े फंड वाले संस्थान ने सिब्बल

को सम्मानित किया था। लेकिन, जैसा कि खेड़ा ने बताया, एपस्टीन ने उस संस्थान को 2002 से 2006 के बीच दान दिया था, जबकि सिब्बल को यह सम्मान 2010 में दिया गया था, जो कई साल बाद की बात है।खेड़ा ने स्पष्ट किया कि भाजपा नेता केवल स्क्रीनशॉट के आधार पर आरोप लगा रहे हैं और इस मुद्दे को उठाकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से जुड़े सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं।केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 11 फरवरी को कहा था कि उन्होंने जेफ्री एपस्टीन से तीन-चार बार मुलाकात की थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी बातचीत पूरी तरह पेशेवर थी और इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म और अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्यों से जुड़ी थीं। पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपस्टीन के आपराधिक मामलों से अपने किसी भी संबंध को बेबुनियाद करार दिया।विश्लेषकों का कहना है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और केंद्रीय मंत्रियों पर बढ़ते दबाव से ध्यान हटाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है। कांग्रेस ने मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर आरोप लगाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक है।

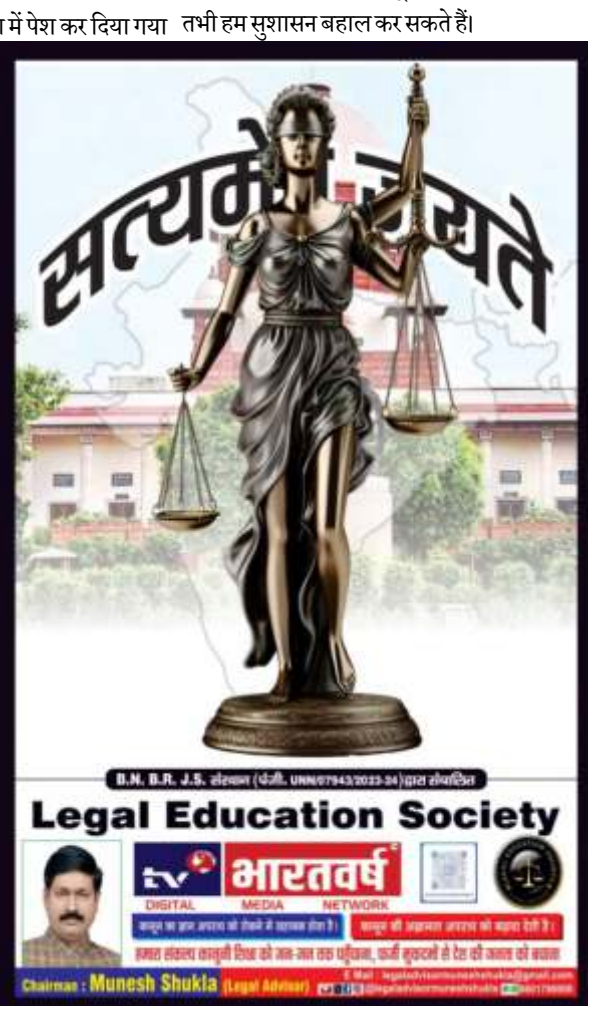

भारतीयों के लिए सुनहरा अवसर:

फ्रेंच सीखकर बढ़ाएं कनाडा PR के चांस

कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी (PR) पाना लाखों लोगों का सपना है, लेकिन 2026 में इमिग्रेशन नियमों में हुए बड़े बदलावों के बाद यह राह पहले से कठिन हो गई है। कनाडाई सरकार ने 2028 तक के अपने इमिग्रेशन प्लान में अस्थायी निवासियों—यानी विदेशी छात्र और वर्कर्स—की संख्या घटाने के संकेत दिए हैं। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास संकट से निपटने के लिए यह कदम जरूरी है।इसी के तहत 2026 में केवल 2.30 लाख टेंपरेरी वर्क परमिट जारी किए जाएंगे, जबकि 2027 और 2028 में यह संख्या और कम होगी। स्टडी परमिट की संख्या भी घटाकर इस साल 1.55 लाख कर दी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधी है।हालांकि, सरकार ने 2026 में 3.80 लाख लोगों को PR देने की योजना बनाई है, लेकिन इन सीमित स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ने वाली है। पहले से कनाडा में रह रहे विदेशी वर्कर्स भी PR के लिए आवेदन करेंगे, जिससे चयन और कठिन हो जाएगा। ऐसे में मजबूत प्रोफाइल ही सफलता की कुंजी बनेगी—और यहीं फ्रेंच भाषा महत्वपूर्ण भूमिका

निभाती है।भारतीय आवेदकों के लिए 'कॉम्प्रिहैंसिव रैंकिंग सिस्टम' (CRS) स्कोर सबसे बड़ी चुनौती है। एक्सप्रेस एंट्री के अधिकांश ड्रॉ में PR पाने के लिए 500 से अधिक स्कोर की आवश्यकता होती है। लेकिन फ्रेंच भाषा जानने वालों के लिए यह बाधा कम हो सकती है।विश्लेषण से पता चलता है कि 2025 से फरवरी 2026 के बीच फ्रेंच भाषा वाले ड्रॉ में कट-ऑफ अपेक्षाकृत कम रहा। दिसंबर 2025 में यह ऐतिहासिक रूप से घटकर 399 तक पहुंच गया, जबकि फरवरी 2026 में 400 स्कोर वाले 8000 उम्मीदवारों को चयनित किया गया। इसके विपरीत सामान्य ड्रॉ में अक्सर 500 से अधिक CRS स्कोर की आवश्यकता होती है।फ्रेंच सीखने का दूसरा लाभ अतिरिक्त अंक हैं। यदि किसी उम्मीदवार को फ्रेंच कैटेगरी ड्रॉ में आमंत्रण नहीं मिलता, तब भी भाषा ज्ञान से CRS स्कोर में 50 अंक तक की बढ़ोतरी हो सकती है, बशर्ते उसे अंग्रेजी का भी ज्ञान हो।सरकार का लक्ष्य क्यूबेक के बाहर भी फ्रेंच भाषी लोगों को बसाना है। 2026 से 5000 PR स्लॉट ऐसे प्रांतों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो फ्रेंच भाषी प्रवासियों को आकर्षित करना चाहते हैं। क्यूबेक के बाहर फ्रेंच भाषी आबादी का लक्ष्य 2029 तक 12% करने की योजना है।इमिग्रेशन विशेषज्ञों के अनुसार, कैटेगरी-बेस्ड ड्रॉ लागू होने के बाद फ्रेंच जानने वालों को स्पष्ट लाभ मिला है। कई मामलों में फ्रेंच कैटेगरी ड्रॉ का CRS स्कोर सामान्य ड्रॉ से 50-80 अंक तक कम रहा है। यही अंतर कई आवेदकों के लिए इंतजार और PR प्राप्ति के बीच निर्णायक साबित हो रहा है।

यूईएफए चैंपियंस लीग: विनीसियस जूनियर पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप, रियाल मैड्रिड ने बेनफिका को 1-0 से हराया

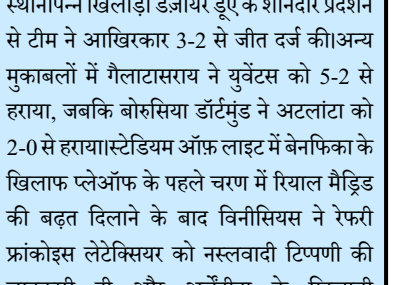

यूईएफए चैंपियंस लीग के प्लेऑफ मुकाबले में फुटबॉल की दुनिया फिर से नस्लवाद के मुद्दे पर गरमा गई है। रियाल मैड्रिड के स्टार फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर ने बेनफिका के खिलाफ मैच के दौरान नस्लीय टिप्पणी किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। यह घटना तब हुई जब विनीसियस ने अपनी टीम के लिए विजयी गोल किया और रियाल मैड्रिड को 1-0 से जीत दिलाई।खेल को तब रोक दिया गया जब विनीसियस ने दावा किया कि एक प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी ने उनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की। रियाल मैड्रिड के डिफेंडर ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड ने मैच के बाद कहा, "अपने करियर में विनीसियस कई बार इस तरह की स्थिति का सामना कर चुके हैं और इसे बखूबी संभाला है। लेकिन उनके प्रति यह व्यवहार जारी रहना और आज रात ऐसा होना फुटबॉल के लिए शर्मनाक है।"इस बीच मौजूदा चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) को मोनाको के खिलाफ जीत के लिए संघर्ष करना पड़ा। पीएसजी एक समय दो गोल से पीछे चल रहा था, लेकिन स्थानापन्न खिलाड़ी डेज़ायर डूए के शानदार प्रदर्शन से टीम ने आखिरकार 3-2 से जीत दर्ज की।अन्य मुकाबलों में गैलाटासराय ने युवेंटस को 5-2 से हराया, जबकि बोरुसिया डॉर्टमुंड ने अटलांटा को 2-0 से हराया।स्टेडियम ऑफ़ लाइट में बेनफिका के खिलाफ प्लेऑफ के पहले चरण में रियाल मैड्रिड की बढ़त दिलाने के बाद विनीसियस ने रेफरी फ्रांकोइस लेटेक्सियर को नस्लवादी टिप्पणी की जानकारी दी और अर्जेंटीना के खिलाड़ी जियानलुका प्रेस्टियानी की ओर इशारा किया।हालांकि, बेनफिका के कोच जोस मोरिन्हो ने कहा कि उनके खिलाड़ी ने नस्लीय टिप्पणी के आरोपों से इनकार किया है।

आईसीसी टी20 रैंकिंग में ईशान किशन की बड़ी छलांग,

17 स्थान ऊपर पहुंचकर बने नंबर 8 बल्लेबाज

साउथ अफ्रीका ने UAE को 6 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार चौथी जीत, सुपर-8 में प्रवेश

टी-20 वर्ल्ड कप के 34वें मैच में साउथ अफ्रीका ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 6 विकेट से हराया। यह टीम की वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत है, जबकि UAE को तीसरी हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों का यह आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला था, जिसमें साउथ अफ्रीका सुपर-8 में पहले ही प्रवेश कर चुकी है और UAE टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग का फैसला किया। UAE ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 122 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका ने 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 123 रन बना कर जीत हासिल कर ली।साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने 36, रयान रिकेल्टन ने 30, ऐडन मार्करम ने 28 और क्विंटन डी कॉक ने 14 रन बनाए। वहीं, जेसन स्मिथ 3 और ट्रिस्टन स्टब्स 6 रन बनाकर नाबाद रहे। UAE की ओर से मुहम्मद फारूक, हैदर अली, मुहम्मद अरफान और मुहम्मद जवादल्लाह को 1-1 विकेट मिला।UAE की

तरफ से अलीशान शराफू ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए, जबकि कप्तान मुहम्मद वसीम ने 22 और ओपनर अर्यांश शर्मा ने 13 रन जोड़े। मुहम्मद अरफान ने 11 रन बनाए।साउथ अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश ने 3 और एनरिक नॉर्त्या ने 2 विकेट लिए, जबकि जॉर्ज लिंडे को 1 विकेट मिला। इस शानदार प्रदर्शन के लिए कॉर्बिन बॉश को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया।इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 में अपनी मजबूत स्थिति कायम रखी है और अब अगले मुकाबलों में नजरें उन्हें फाइनल की ओर बढ़ते देख रही हैं।

जम्मू-कश्मीर ने बंगाल को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई

जम्मू-कश्मीर की क्रिकेट टीम ने बुधवार को भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय लिखा। ईडन गार्डन्स में खेले गए सेमीफाइनल के चौथे दिन, जम्मू-कश्मीर ने दो बार की चैंपियन बंगाल को छह विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया। बंगाल द्वारा दिए गए 126 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए जम्मू-कश्मीर ने 34.4 ओवर में चार विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया।जम्मू-कश्मीर की जीत में तेज गेंदबाज आकिब नबी का योगदान अहम रहा। उन्होंने मैच में नौ विकेट लिए और बंगाल की जीत की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। इसके अलावा आईपीएल स्टार अब्दुल समद और युवा बल्लेबाज वंशज शर्मा की बेहतरीन नाबाद पारियों ने टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। समद ने 22 वर्षीय वंशज को विजयी रन बनाने का मौका दिया, जिसे वंशज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर भुनाया। वंशज ने नाबाद 43 रन बनाए जबकि समद 30 रन पर रहे।जम्मू-कश्मीर ने 1959-60 में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था, लेकिन उसे दशकों तक मजबूत दावेदार नहीं माना जाता था। इस सत्र से पहले उसने 334 रणजी मैचों में से केवल 45 ही जीते थे। 1982-83 में अपनी पहली जीत दर्ज करने के बाद टीम को लगातार सफलता नहीं मिली। हालांकि 2013-14 में क्वार्टर फाइनल में पहुंचना और 2015-16 में मुंबई को हराना इसके प्रमुख क्षण रहे।इस सत्र में कोच अजय शर्मा और कप्तान पारस डोगरा के नेतृत्व में टीम ने अपने विश्वास को परिणामों में बदल दिया। शुरुआती मैच में मुंबई से हार के बाद जम्मू-कश्मीर ने राजस्थान के खिलाफ पारी की जीत और दिल्ली तथा हैदराबाद को हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश को 56 रन से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई

पंजाब प्रीमियर लीग 2026:

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा करेंगे टी20 धमाका

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) जून 2026 में पंजाब प्रीमियर लीग (पीपीएल) का आयोजन करने जा रहा है। यह लीग अब नए नाम और नए प्रारूप के तहत खेली जाएगी। पीपीएल की सभी छह टीमें फ्रेंचाइजी आधारित होंगी और खिलाड़ियों का चयन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। पीसीए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस टूर्नामेंट में केवल पंजाब में पंजीकृत खिलाड़ी ही भाग लेंगे।लीग में पंजाब के सभी प्रमुख खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। भारतीय टेस्ट और सीमित ओवरों के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, भारत के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, रमनदीप सिंह, नेहाल वढेरा, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह और प्रभसिमरन सिंह जैसे अनुभवी पंजाब खिलाड़ी भी मुख्य खिलाड़ियों में शामिल होंगे। वर्तमान भारतीय अंडर-19 टीम के युवा खिलाड़ी विहान मल्होत्रा भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे।पीपीएल केवल वरिष्ठ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। अंडर-23 खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा, जिससे युवा प्रतिभाओं को मंच मिल सके। लीग में पंजाब के कई उभरते हुए क्रिकेटर भी खेलेंगे, जिन्होंने घरेलू और आईपीएल स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। मयंक मार्कंडे, अश्वनी कुमार, गुरनूर बराड़, हरनूर सिंह, रमन धीर और हरप्रीत बराड़ जैसे खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जिससे प्रतियोगिता और रोमांच बढ़ेगा। इसके अलावा, सलिल अरोरा, रघु शर्मा और कई अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी पीपीएल का हिस्सा होंगे। यह नई फ्रेंचाइजी आधारित लीग पंजाब के क्रिकेट को और मजबूती देने के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों के विकास और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पीपीएल का उद्देश्य न केवल मनोरंजन प्रदान करना है, बल्कि राज्य की क्रिकेट प्रतिभाओं को सामने लाना और उन्हें बड़े मंच पर प्रदर्शन का अवसर देना भी है।

15000 स्कूलों में खुलेंगे डिजिटल कंटेंट सेंटर, 'गेमिंग और कॉमिक्स' की लैब्स बनेंगी

क्लाउड, डेटा सेंटर और AI पर फोकस

बजट 2026 में 'ऑरेंज इकॉनमी' के तहत गेमिंग, AI और सेमीकंडक्टर पर बड़ा निवेश किया गया है. 15000 स्कूलों में AVGC लैब्स की स्थापना और 10,000 टेक फेलोशिप के जरिए सरकार डिजिटल कंटेंट और तकनीकी रिसर्च को करियर के मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है.

मुन्ज़िर अहमद, आजतक

Budget 2026 से टेक सेक्टर को क्या मिला? (Photo: ITG)

बजट 2026 में इस बार एक बात बिल्कुल साफ नजर आई. सरकार अब टेक्नोलॉजी को सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि देश की ग्रोथ का इंजन मान रही है. इसे ऑरेंज इकॉनमी के कैटिगरी में माना जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और डिजिटल स्किल्स पर खास फोकस दिखा. इसका असर आने वाले समय में छात्रों, गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और आम डिजिटल यूजर्स तक दिख सकता है.

बजट का सबसे मजबूत संकेत गेमिंग और क्रिएटर इकोनॉमी को लेकर आया. सरकार ने ऐलान किया कि देश के हजारों स्कूलों और कॉलेजों में AVGC यानी एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी. सरकार का मानना है कि अब गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला सेक्टर बन चुका है.

फॉरेनर ने लगाए 'भारत माता की जय' के नारे

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. कभी वो आपको खूब हंसाते हैं, तो कभी आपको एक दम हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हाल के समय में आग की तरह फैल रहा है. ऑस्ट्रेलियाई से आए एक यात्री इंकन मैकनॉघ्ट ने महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में घूमने के लिए गए थे. इसे लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर लोग बेहद खुश हो रहे हैं.

रेडिट पर बेंगलुरु के कैब ड्राइवर की कहानी वायरल

16 घंटे ड्राइविंग, बचत सिर्फ 1000 रूपए

बेंगलुरु के एक कैब ड्राइवर की कहानी रेडिट (Reddit) पर वायरल हो रही है. लंबे समय तक बेरोजगार रहने, बिजनेस में नुकसान होने के बाद कैब ड्राइवर बनने का फैसला किया. रेडिट पर उसने कैब ड्राइवर की जिंदगी में दिक्कतें, स्ट्रेस, रोजाना कमाई और बजट सब का हिसाब दिया. रेडिट पर ड्राइवर बताता है कि वो रोजाना 16 घंटे काम करता है. किसी रोज नागा नहीं और उसकी जिंदगी पूरी तरह से फंस चुकी है. रोजाना 16 घंटे ड्राइविंग करने के बाद भी बमुश्किल 1000 रुपये हाथ में बचने थे. ड्राइवर ने अपनी पोस्ट में पूछा - क्या यही जिंदगी है. ड्राइवर ने बताया कि

वह लगभग डेढ़ साल तक नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला. इसी दौरान उसने बिजनेस शुरू किया, लेकिन वह भी असफल रहा. इसके बाद वह लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंस गया. आखिर में मजबूरी में उसने 1500 रूपये प्रतिदिन किराये पर एक येलो बोर्ड कार ली और पिछले महीने से ड्राइविंग शुरू की.

कश्मीर की वादियों से वायरल हुआ वीडियो

दुबई के मशहूर कंटेंट क्रिएटर ने दिखाई घाटी की बर्फीली जन्नत

UAE के लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर खालिद अल अमेरी इन दिनों अपनी कश्मीर यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को बर्फीली जन्नत बताया.

उनका कहना है कि दुबई जैसी रेगिस्तानी सरजमीं से सिर्फ चार घंटे की उड़ान आपको एक ऐसी वादी में ले आती है, जहां बर्फ की सफेद चादर किसी दूसरी ही दुनिया का अहसास कराती है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. वीडियो की शुरुआत में वह बर्फबारी के बीच हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते हैं. स्क्रीन पर पहले लिखा आता है-दिस इज नॉट स्विट्जरलैंड और

कुछ ही पल बाद टेक्स्ट बदलकर होता है -दिस इज कश्मीर. कैमरा घूमते ही बर्फ से ढकी घाटी की खूबसूरती वीडियो में उभरकर सामने आती है. एक नजारे में अल अमेरी स्थानीय कश्मीरी डिश का स्वाद लेते भी दिखाई देते हैं. अपने दूसरे वीडियो में वह कश्मीर की खूबसूरती दिखाते हुए कहते हैं कि दुनिया की जन्नत यहीं है, अब मुझे समझ में आ गया क्यों... मा शा अल्लाह. वीडियो पर उनकी पार्टनर और तमिल अभिनेत्री Sunaina Yella ने भी प्रतिक्रिया दी.

सिद्धांत चतुर्वेदी का सपना युवराज सिंह की बायोपिक में निभाना चाहते हैं मुख्य भूमिका

एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'दो दीवाने सहर में' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में उनके साथ मृणाल ठाकुर हैं, और यह 20 फरवरी को रिलीज होने वाली है। हाल ही में प्रमोशन के दौरान सिद्धांत ने अपने ड्रीम रोल के बारे में भी खुलकर बात की, जो लंबे समय से उनके दिल के करीब है।जब उनसे पूछा गया कि वे किस क्रिकेटर की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाना चाहेंगे, तो उनका जवाब तुरंत और बिना हिचकिचाहट के था—भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह। सिद्धांत युवराज सिंह के बड़े फैन हैं और उनकी जिंदगी से काफी इंस्पायर महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, "मैं बायोपिक करने को बिल्कुल तैयार हूं। मैं हमेशा इसे करने के लिए रेडी हूं। मैं 2019 से ये बात कहता आ रहा हूं और आज भी कह रहा हूं। युवराज सिंह का सफर कमाल का रहा है, बिल्कुल रोलरकोस्टर की तरह। मैंने उनके हर मैच में उन्हें सराहा है, उनके खेल, जीवनशैली और कठिन हालातों का सामना करने के तरीके ने मुझे प्रेरित किया है। वे एक आइकन हैं और दुनिया को उनकी कहानी जाननी चाहिए।"सिद्धांत का क्रिकेट से नाता उनकी करियर की शुरुआत में ही जुड़ गया था। उन्होंने नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज Inside Edge में काम किया, जिसने क्रिकेट की दुनिया के अंधेरे और जटिल पहलुओं को दर्शाया। इसके बाद वे फोन भूत, गहराइयां और खो गए हम कहां जैसी फिल्मों में भी नजर आए।युवराज सिंह की जिंदगी की बात करें तो वे क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। मैदान पर उनके किस्से और पर्सनल जीवन दोनों ही चर्चा में रहे। उनके पिता योगराज सिंह ने उन्हें प्रशिक्षित किया, लेकिन पिता और मां के अलग होने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, उनकी हेजल कीच संग लव स्टोरी भी बेहद चर्चित रही।हाल ही में सिद्धांत ने बॉलीवुड में अपने 10 साल पूरे किए। उन्होंने माना कि वे नेटवर्किंग या पीआर में कभी खास अच्छे नहीं रहे और हमेशा अपने काम को ही पहचान बनाने का जरिया माना। उन्होंने कहा, "मैं नेटवर्किंग में अच्छा नहीं हूं। मुझे नहीं पता खुद को कैसे पेश किया जाए। क्या मेरा काम ही लोगों को मेरी सच्चाई बताने का तरीका नहीं है? मासूमियत, सादगी, असलियत और मिनिमलिज्म आने वाले 15 सालों में जिंदगी का नया तरीका होंगे।"सिद्धांत की यह सोच और युवराज सिंह के लिए उनका जुनून, दर्शकों को उनके अगले कदम का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर रहा है।

लखनऊ यूनिवर्सिटी में मोहन भागवत के आगमन पर हंगामा

लखनऊ यूनिवर्सिटी में RSS प्रमुख मोहन भागवत के आगमन पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें काबू में किया। भागवत ने सामाजिक सद्भाव, जातिवाद उन्मूलन, मातृशक्ति और राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए अपने विचार साझा किए।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ यूनिवर्सिटी में बुधवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के आगमन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। NSUI, समाजवादी छात्र सभा और भीम आर्मी से जुड़े छात्रों ने 'गो बैक मोहन भागवत' के नारे लगाना शुरू किया।छात्रों को रोकने के प्रयास में पुलिस और छात्रों के बीच खींचतान हुई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन जीप और बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। कई छात्र लेट जाने पर पुलिस ने उन्हें टांगकर बसों में बिठाया। इसके बाद मोहन भागवत का कार्यक्रम शांतिपूर्वक शुरू हुआ।NSUI कार्यकर्ता शुभम यादव ने कहा कि संघ से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की अनुमति दी जा रही है, जबकि विपक्षी छात्र संगठनों को हॉल तक जाने नहीं दिया जाता। उन्होंने UGC विवाद का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, लेकिन RSS प्रमुख की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया।मोहन भागवत दो दिवसीय लखनऊ प्रवास पर हैं। आज वे लखनऊ यूनिवर्सिटी में संगोष्ठी में शामिल हुए और इसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मंगलवार को वे निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल हुए थे।उन्होंने सामाजिक सद्भाव और विविधता पर अपने विचार साझा किए। UGC गाइडलाइन के संबंध में उन्होंने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। अगर कानून गलत है, तो उसे बदलने का उपाय भी होना चाहिए। कानून जातियों के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए।छात्रों के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस सुबह 5 बजे ही समाजवादी छात्र सभा के सदस्य तौकील गाजी के हॉस्टल पहुंच गई और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। कई अन्य सदस्यों को हिरासत में लेकर हसनगंज थाना भेजा गया।भागवत ने मुगल और अंग्रेज शासन के बावजूद हिंदू धर्म और संस्कृति की मजबूती का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठे कुछ लोग हमारी सद्भावना के विरुद्ध योजना बना रहे हैं, जिससे सावधान रहना जरूरी है। जातिवाद की विषमता को समाज को मिलकर दूर करना होगा।उन्होंने हिंदू धर्म में लौट रहे लोगों का ध्यान रखने, घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर चिंता जताते हुए कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने चाहिए।मातृशक्ति पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि घर और परिवार का आधार महिलाएं हैं। महिला अबला नहीं, बल्कि असुर मर्दिनी है। पश्चिम में महिलाओं को केवल पत्नी के रूप में देखा जाता है, जबकि हमारी परंपरा में उन्हें माता माना जाता है।सामाजिक मंच और मुस्लिम समुदाय के RSS से जुड़ने के संबंध में उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए उनका मंच बनाया गया। भारत निकट भविष्य में विश्व को मार्गदर्शन देगा और विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान भारत के पास ही है।इस कार्यक्रम में छात्रों के विरोध और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही मुद्दे प्रमुख रहे। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए प्रदर्शन को काबू में किया, वहीं RSS प्रमुख ने अपने संबोधन में सामाजिक सद्भाव, महिलाओं की भूमिका, जातिवाद और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया।कुल मिलाकर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मोहन भागवत का आगमन न केवल छात्रों के विरोध की वजह से चर्चा में रहा, बल्कि उनके विचारों और दिशा-निर्देशों ने भी समाज और राजनीति में नया विमर्श पैदा किया।

लखनऊ में 17 दिन बाद मिला लापता युवक का शव

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में मंगलवार शाम इंदिरा नहर में एक युवक का शव उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान प्रियांशु (21) निवासी ग्राम कबीरपुर थाना गोसाईगंज के रूप में हुई है। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए एक युवती और उसके प्रेमी पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 7 साल पुराने प्रेम संबंध में आई दरार ने प्रियांशु की जान ले ली। भाई सुधीर ने बताया कि 31 जनवरी की रात प्रियांशु गांव के पास स्थित अल्फा पब्लिक कॉलेज में सोने गया था। वह अक्सर सुबह 7 बजे तक घर लौट आता था, लेकिन 1 फरवरी को सुबह 10 बजे तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कॉलेज के गार्ड ने बताया कि वह सुबह करीब 7 बजे वहां से निकल गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो 2 फरवरी को गोसाईगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि इंदिरा नहर में एक युवक का शव बह रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसकी पहचान प्रियांशु के रूप में की। परिजनों का दावा है कि शव पर चेहरे सहित कई जगह चोट के निशान थे। उनका कहना है कि शव की हालत देखकर लग रहा था कि मौत कुछ ही दिन पहले हुई है, जबकि प्रियांशु 17 दिन से लापता था। भाई सुधीर के अनुसार, प्रियांशु का पास के गांव की ही एक युवती से करीब सात साल से प्रेम संबंध था। दोनों एक जाति थे और शादी की बात भी चल रही थी। इस दौरान लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। हाल के दिनों में युवती का संबंध दूसरे लड़के से हो गया।

लखनऊ महिला अग्निवीर भर्ती रैली में दौड़ और लॉन्ग जंप के दौरान 4 अभ्यर्थी घायल, अस्पताल पहुंचाए गए

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में महिला अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा की चुनौतियां सामने आईं। दौड़ और एथलेटिक टेस्ट के दौरान तीन अभ्यर्थी दौड़ते-दौड़ते गिरकर बेहोश हो गईं, जबकि लॉन्ग जंप के अभ्यास के दौरान एक अन्य अभ्यर्थी के पैर में मोच आ गई। सभी घायलों को मौके पर मौजूद एंबुलेंस से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।रैली में अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ आठ मिनट के अंदर पूरी करनी थी। निर्धारित समय से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ग्रेड-वन, जबकि आठ मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ग्रेड-टू दिया गया। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को हाई जंप और लॉन्ग जंप के अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया गया। हाई जंप में 3 फीट की ऊंचाई और लॉन्ग जंप में 10 फीट की दूरी तय करनी थी। इन दोनों टेस्टों में अभ्यर्थियों को तीन-तीन मौके दिए गए।भर्ती रैली का आयोजन लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर एंड कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की करीब 1,000 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस रैली में वही उम्मीदवार शामिल हुए, जिन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन सीईई परीक्षा पास की थी। सभी अभ्यर्थियों को पहले ही ईमेल के जरिए एडमिट कार्ड भेजे गए थे, ताकि परीक्षा के दिन कोई भ्रम या देरी न हो।रैली के आयोजकों ने बताया कि सभी सुरक्षा और चिकित्सा इंतजाम पहले से ही सुनिश्चित किए गए थे। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी टेस्टों में भाग लें। भर्ती अधिकारियों ने यह भी कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।इस तरह, महिला अग्निवीर भर्ती रैली में प्रतिस्पर्धा और उत्साह दोनों देखने को मिले, लेकिन कुछ उम्मीदवारों की चोटें यह याद दिलाती हैं कि शारीरिक चुनौतियों के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए।

लखनऊ में टीचरों ने बच्चों पर फूल बरसाए

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गईं। पहले दिन दोनों कक्षाओं की हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। हाईस्कूल का पेपर सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक संपन्न हुआ, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चली।परीक्षा केंद्रों पर छात्रों का भव्य स्वागत किया गया। बच्चों पर फूल बरसाए गए, तिलक लगाया गया और मिठाई-टॉफी खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। जियामऊ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने परीक्षा से पहले छात्राओं का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।हाईस्कूल की परीक्षा देकर बाहर आए छात्रों ने बताया कि प्रश्नपत्र आसान था और परीक्षा अच्छी तरह से हुई। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा को लेकर जो डर था, वह अब खत्म हो गया है। लखनऊ में आदर्श कारागार समेत 121 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,03,088 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं।परीक्षा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। तीन स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के अलावा सात जोनल, 11 सेक्टर और 121 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 121 परीक्षा केंद्रों और उतने ही बाहरी केंद्रों पर व्यवस्थापक लगाए गए हैं। कुल 3,600 कक्ष निरीक्षक परीक्षा की सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करेंगे।विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्थित तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था छात्रों के लिए परीक्षा को सुरक्षित और तनावमुक्त बनाने में मदद करती है। छात्रों और अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की। इस तरह, यूपी बोर्ड की परीक्षा का पहला दिन सुचारू और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ, जो आगामी दिनों के लिए उत्साहजनक संकेत देता है।

लखनऊ में मांझे से गर्दन कटने के मामले में FIR

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में थाना हुसैनगंज क्षेत्र में शेर वाली कोठी के पास रहने वाले 29 वर्षीय मोहम्मद मुशर्रफ 12 को चाइनीज मांझे का शिकार हो गए थे। वह अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ बाइक से हुसैनगंज से लालकुआं जा रहे थे। उनकी शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पतंग उड़ाने वाले की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही उनकी बाइक फ्लाईओवर पर पहुंची, अचानक चाइनीज मांझा सामने आ गया। मुशर्रफ संभल पाते उससे पहले मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया। तेज धार मांझे से उनकी गर्दन कट गई और दर्द से घबराकर उन्होंने अचानक ब्रेक लगा दी। बाइक स्लिप हो गई और तीनों फ्लाईओवर पर ही गिर पड़े। हादसे में मुशर्रफ गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि उनकी पत्नी को भी चोटें आईं। छोटी बच्ची बाल-बाल बच गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत मदद की। मुशर्रफ और उनकी पत्नी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद मुशर्रफ की हालत स्थिर है।

लखनऊ में सीएसआई टावर लिफ्ट कांड में नया मोड़

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के सीएसआई टावर में हाल ही में हुए लिफ्ट हादसे को लेकर ठेकेदार और प्राधिकरण के बीच विवाद गरमाया है। निरीक्षण के दौरान ठेकेदार असलम आगा ने एलडीए को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लिफ्ट गिरने की घटना वास्तविक रूप में नहीं हुई थी।17 फरवरी को एलडीए के मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह को लिखे पत्र में ठेकेदार ने दावा किया कि लिफ्ट झटके ले रही थी, लेकिन इसका कारण अस्थायी बिजली कनेक्शन के चलते वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होना था। इसी दौरान लिफ्ट की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और लिफ्ट स्वतः रुक गई। ठेकेदार ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा प्रणाली काम न करती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन लिफ्ट पूरी तरह नीचे नहीं गिरी।ठेकेदार ने पत्र में यह भी कहा कि उसकी जिम्मेदारी केवल लिफ्ट की आपूर्ति और स्थापना तक सीमित थी। अभी तक लिफ्ट का विधिवत कमिश्निंग और हैंडिंग ओवर नहीं हुआ है। स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना एलडीए की जिम्मेदारी थी, जो नहीं दिया गया। अगर स्थायी कनेक्शन समय पर मिलता तो लिफ्ट में यह समस्या नहीं आती।वहीं, एलडीए की ओर से वीसी प्रथमेश कुमार और मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह ने बयान दिया है कि लिफ्ट झटके के साथ नीचे की ओर गिरती रही और बीच में अटक गई। उन्होंने कहा कि यदि लिफ्ट बीच में अटकी नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वीसी प्रथमेश कुमार ने 13 फरवरी को अधिकारियों के साथ लिफ्ट का निरीक्षण भी किया था।अब इस मामले में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब लिफ्ट का औपचारिक हैंडिंग ओवर नहीं हुआ और स्थायी बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध नहीं था, तो निरीक्षण और परीक्षण किस आधार पर किया गया। एलडीए और ठेकेदार दोनों ही अपनी-अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करने में जुटे हुए हैं। इस विवाद ने लिफ्ट सुरक्षा और निर्माण प्रक्रिया में खामियों को भी उजागर किया है।विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सुरक्षा प्रणाली का काम करना ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी के स्पष्ट निर्धारण और औपचारिक परीक्षण के बिना निरीक्षण करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। इस घटना ने टावर परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों और निरीक्षण प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।सुरक्षा विशेषज्ञों और निर्माण इंजीनियरों का सुझाव है कि आगे से ऐसे सभी टावर और ऊंची इमारत परियोजनाओं में लिफ्ट की स्थापना और परीक्षण की प्रक्रिया को और भी अधिक कड़ा किया जाए। इसमें स्थायी बिजली कनेक्शन, कमिश्निंग, हैंडिंग ओवर और नियमित निरीक्षण अनिवार्य होना चाहिए। यह कदम न केवल भविष्य में हादसों को रोकने में मदद करेगा, बल्कि ठेकेदार और प्राधिकरण के बीच जिम्मेदारी विवाद को भी कम करेगा। इसके साथ ही, लिफ्ट संचालन में आने वाले किसी भी तकनीकी या सुरक्षा संबंधित खतरों की समय पर पहचान और समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

फीस बकाया पर रोका एडमिट कार्ड, परीक्षा से वंचित छात्र डिप्रेशन में

टीवी भारतवर्ष उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बोर्ड परीक्षा से पहले एक प्राइवेट स्कूल की मनमानी की वजह से एक छात्र का पेपर छूट गया। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल ने एक महीने की फीस जमा न होने की वजह से छात्र का प्रवेश पत्र रोक लिया, जिससे छात्र की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया।यह पूरा मामला जनपद के अमेठी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर फुलवारी स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अंशुमान त्रिपाठी का है। वह अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल एडमिट कार्ड लेने पहुंचा था, लेकिन स्कूल की ओर से एक महीने की फीस जमा न होने के चलते उसे बिना एडमिट कार्ड के वापस लौटा दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रवेश पत्र न मिलने के कारण छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सका।घर लौटने के बाद छात्र की तबीयत अचानक खराब हो गई। परिजनों के मुताबिक, एडमिट कार्ड न मिलने और परीक्षा छूट जाने के तनाव में वह मानसिक रूप से परेशान हो गया। आनन-फानन में उसके अभिभावक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि छात्र एंजायटी और डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया, लेकिन परिवार अब भी सदमे में है।छात्र के पिता लोकेश त्रिपाठी ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल ने जबरन पैसा मांगने के लिए एडमिट कार्ड रोका और मनमानी की। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण समय पर प्रवेश पत्र रोकना पूरी तरह अनुचित है और इससे छात्र के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना को लेकर स्कूल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्र के साथ ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो।यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। अभिभावकों का कहना है कि फीस विवाद को परीक्षा से जोड़ना उचित नहीं है। उनका मानना है कि यदि फीस बकाया थी तो उसके लिए अलग से वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी, लेकिन परीक्षा में शामिल होने से रोकना छात्रों के हितों के खिलाफ है। शिक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस तरह की घटनाएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं और संस्थानों को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए।वहीं, इस मामले को लेकर प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। एडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि छात्र के घर पर उसका एडमिट कार्ड उसकी माता को दे दिया गया है। साथ ही अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।घटना ने शिक्षा व्यवस्था और निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासनिक जांच जारी है और परिजन निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद लगाए हुए हैं। स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-

वाराणसी दालमंडी में बुलडोजर की कार्रवाई: तीन जर्जर मकानों को किया जमींदोज

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में बुधवार को एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। इस बार नगर निगम ने जर्जर घोषित किए गए तीन मकानों पर ध्वस्तीकरण कार्य किया। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्रवाई में मकान संख्या सीके 62/2 पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह मकान पहले आंशिक रूप से तोड़ा गया था, लेकिन आज इसे पूरी तरह जमींदोज किया जा रहा है।नगर निगम की इस कार्रवाई के लिए करीब 200 पुलिसकर्मी और आला अधिकारी मौके पर तैनात किए गए हैं। एडीएम सिटी आलोक वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई संपन्न हो रही है। मौके पर एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी भी मौजूद रहे और पूरे ध्वस्तीकरण कार्य पर नजर रखी।एसीपी अतुल अंजान ने बताया कि नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित किए गए मकानों को तोड़ने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, स्थानीय लोगों और राहगीरों को डायवर्ट किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। उन्होंने कहा कि पहले मैन्युअल कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा।पीडब्ल्यूडी के अभियंता केके सिंह ने बताया कि दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तक 40 से अधिक मकानों की रजिस्ट्री करवा ली गई है और 30 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा संबंधित मकान मालिकों को दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कई और मकानों की रजिस्ट्री प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जल्द ही उन पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।दालमंडी में यह चौड़ीकरण कार्य मुख्यतः सड़क और आवागमन सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पुराने और जर्जर मकानों को हटाकर क्षेत्र में सड़क का विस्तार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से न केवल स्थानीय आवागमन आसान होगा, बल्कि आसपास के व्यापारिक और आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा और सुविधा भी बढ़ेगी।मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था से बचने के लिए सभी सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। साथ ही स्थानीय निवासियों को पहले ही कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी, ताकि उन्हें समय रहते अपने सामान और दस्तावेज सुरक्षित करने का मौका मिले।स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में दालमंडी में लगातार चौड़ीकरण और सफाई के लिए कार्रवाई चल रही है। कुछ मकान मालिकों ने मुआवजा राशि को लेकर संतोष व्यक्त किया है, जबकि कुछ ने शिकायत की है कि उन्हें मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली। अधिकारियों ने कहा कि मुआवजा वितरण प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाएगी।नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम लगातार दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना पर नजर रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। इस बीच, पुलिस और प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे ध्वस्तीकरण क्षेत्र में न आएं और मार्ग डायवर्ट का पालन करें। कुल मिलाकर, वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में आज की कार्रवाई परियोजना की निरंतरता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम मानी जा रही है। तीन जर्जर मकानों के ध्वस्तीकरण के साथ ही इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे।

तीन मामलों में लापरवाही भारी पड़ी, खजनी के SDO भोलानाथ निलंबित

टीवी भारतवर्ष गोरखपुर

गोरखपुर में विद्युत विभाग ने सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए खजनी उपखंड के एसडीओ भोलानाथ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन के सीधे निर्देश पर की गई। विभागीय जांच में उपखंड के तीन अलग-अलग स्थानों पर गंभीर गड़बड़ियां और लापरवाही सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया।विभागीय सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया, मीटर रीडिंग, बिलिंग व्यवस्था और लाइन मेंटेनेंस से संबंधित अनियमितताएं पाई गईं। इन मामलों में उपभोक्ताओं की शिकायतें भी सामने आई थीं, जिसके बाद विस्तृत जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच में दो जूनियर इंजीनियरों (जेई) की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, जिन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है।जांच आगे बढ़ने पर उपखंड के एसडीओ भोलानाथ की जिम्मेदारी और निगरानी में गंभीर चूक सामने आई। विभागीय रिपोर्ट में उनकी लापरवाही की पुष्टि होने के बाद चेयरमैन ने तत्काल निलंबन के आदेश जारी किए। विभाग का मानना है कि उपखंड स्तर पर प्रशासनिक निगरानी में कमी के कारण ये गड़बड़ियां लंबे समय तक जारी रहीं।यूपीपीसीएल चेयरमैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विद्युत विभाग में किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।विभाग ने बताया कि तीनों मामलों की जांच पूरी कर ली गई है और दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। यदि आगे की जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलते हैं, तो मामला विजिलेंस या पुलिस को सौंपा जा सकता है।एसडीओ के निलंबन के साथ ही खजनी उपखंड में नए प्रभारी एसडीओ की नियुक्ति कर दी गई है, ताकि बिजली आपूर्ति और संबंधित सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। विभागीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।इस कार्रवाई को विभाग के भीतर अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और सेवा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आगे भी सख्त कदम उठाए जाने के संकेत दिए गए हैं।साथ ही, विभाग ने सभी उपखंड अधिकारियों को कार्यप्रणाली की आंतरिक समीक्षा करने और लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव में किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की जनपदीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित जनपद उन्नाव के नोडल अधिकारी डॉ. गगनेश शर्मा, जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद के निदेशक भी हैं, उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उप कृषि निदेशक रवि चन्द्र प्रकाश ने योजना के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत दलहन एवं तिलहन फसलों को शामिल करते हुए किसानों के बीच प्रमाणित बीजों का वितरण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों का प्रमाणीकरण कराया जाए, जिससे बाजार में उनकी विश्वसनीयता बढ़े। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्रेता एवं विक्रेता की संयुक्त बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही, हॉट मार्केटिंग की अवधारणा पर चर्चा करते हुए कहा कि ग्राम स्तर पर स्थापित हॉट मार्केटिंग केंद्रों का सदुपयोग किया जाए और ब्लिंकिट तथा स्विगी जैसी कंपनियों की तर्ज पर नेटवर्क तैयार कर कृषि उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाएं।

यूपी के ग्रामीण इलाकों में 'अपना दल' का UGC-चौपाल कार्यक्रम शुरू

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

देश में यूजीसी कानून-2026 के विरोध के बाद उसे लागू करने के समर्थन में राजनीतिक दल उतर आए हैं। अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता अब गांव-गांव यूजीसी चौपाल लगाएंगे। लोगों से मिलकर यूजीसी के लागू होने और नई गाइडलाइन से सुरक्षा को बताएंगे। अपना दल कमेरावादी के साथ विभिन्न सामाजिक एवं छात्र युवा संगठन जिला मुख्यालय वाराणसी पर जुटे। शास्त्री घाट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यूजीसी विनियम लागू करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। चौपाल के साथ चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। कचहरी स्थित डॉ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन के एसीएम प्रथम को पत्र सौंपकर कहा कि जब तक यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू नहीं होता है, तब तक आंदोलन करेंगे। वाराणसी में बुधवार को शास्त्रीघाट पर प्रदर्शनकारियों ने 'यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू करो', 'हम सबका है ऐलान, सबको शिक्षा सबको मान', शिक्षण संस्थानों में वंचितों का उत्पीड़न बंद करो', आदि नारे लगाए। हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

उन्नाव डीएम ने पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा की

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में जनपद में योजना की प्रगति, स्थापित सोलर संयंत्रों की स्थिति और उपभोक्ताओं को मिल रहे लाभों का विस्तृत जायजा लिया गया। यूपीनेडा के प्रभारी परियोजना अधिकारी नेपाल सिंह ने बताया कि जनपद में वेंडरों द्वारा कई घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने योजना के निर्धारित लक्ष्यों, अनुदान व्यवस्था और तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वेंडर को आवंटित लक्ष्य के अनुसार प्राथमिकता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक घरों में सोलर सिस्टम लग सकें। जिलाधिकारी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को उपभोक्ताओं के लिए महत्वाकांक्षी और लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह घरेलू विद्युत कनेक्शन धारकों के लिए बिजली बिल कम करने और केंद्र सरकार के अनुदान का लाभ उठाने का सुनहरा अवसर है। जिलाधिकारी ने जनपद में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए कि वे वेंडरों द्वारा संयंत्र स्थापना के बाद उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजना से संबंधित किसी भी फर्म या उपभोक्ता की समस्या को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर उसका निराकरण कर सकें।

मायावती का विपक्ष पर तीखा हमला, बोलीं- हमें सत्ता से दूर रखने की रची जा रही है साजिश

मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को विपक्ष की साजिशों से सतर्क रहने को कहा। उन्होंने अंबेडकरवादी आंदोलन को मजबूत करने और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व गरीब वर्गों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। बसपा 2027 चुनाव में मजबूत वापसी की तैयारी में है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। इसी क्रम में बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बसपा को सत्ता से दूर रखने के लिए नई-नई साजिशें रच रहे हैं और विभिन्न हथकंडे अपना रहे हैं।एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने अपने समर्थकों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पार्टी को कमजोर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर सावधान और संगठित रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में अंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को एकजुट होकर अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।मायावती ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आंदोलन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आत्मसम्मान की प्राप्ति और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष जरूरी है। उन्होंने राज्य और देश के सभी अंबेडकरवादियों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर आंदोलन को नई ऊर्जा दें। उनका कहना था कि चुनावी माहौल में विरोधी दल भ्रम फैलाने और बसपा के जनाधार को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए संगठनात्मक मजबूती समय की मांग है।उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, विरोधियों के प्रयास और तेज होंगे। "हमें सत्ता से दूर रखने के लिए हमारे खिलाफ साजिशें रची जाएंगी। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा को मजबूती से रखें," उन्होंने कहा।2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बसपा ने राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों की समीक्षा पर चर्चा की जाएगी। मायावती ने बताया कि चुनाव के लिए अब अधिक समय शेष नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चल रहे एसआईआर (SIR) अभ्यास के कारण पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में देरी हुई है, लेकिन संगठन इसे शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्षी दलों द्वारा अपनाई जा रही नई रणनीतियों और साजिशों के प्रति पूरी तरह सजग रहें तथा संगठन को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को विफल करें।बसपा प्रमुख ने स्पष्ट किया कि पार्टी का मुख्य फोकस गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर रहेगा। उन्होंने कहा कि इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज भी चिंताजनक बनी हुई है। इसके साथ ही किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों और अन्य कामकाजी लोगों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकारों के साथ-साथ पिछली सरकारों के दौरान भी इन वर्गों की समस्याएं जस की तस बनी रही हैं। उन्होंने कहा कि बसपा इन मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाएगी और जनता के बीच जाकर बताएगी कि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करना ही पार्टी का मूल उद्देश्य है।गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और पार्टी केवल एक सीट पर सिमट गई थी।

तिरुपति अस्पताल में नवजात की मौत: परिजनों का आरोप गलत इलाज और ऑपरेशन को बताया कारण

टीवी भारतवर्ष कुशीनगर

कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के DCF चौक स्थित तिरुपति अस्पताल में नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में गलत इलाज और गलत ऑपरेशन के कारण नवजात की मौत हुई। प्रसूता (मां) की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वह अस्पताल में भर्ती है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार, प्रसूता सरकारी अस्पताल में भर्ती थीं, जहां से आशा वर्कर ने उन्हें तिरुपति अस्पताल रेफर किया था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन परिजनों का दावा है कि ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया गया। नवजात शिशु को गंभीर हालत में निकाला गया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि अस्पताल ने पहले सही जानकारी नहीं दी और बाद में भी मौत का सही कारण नहीं बताया। परिजन अस्पताल के बाहर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आशा वर्कर ने सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल भेजा, लेकिन वहां गलत इलाज हुआ। उन्होंने मांग की है कि अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज हो, मुआवजा दिया जाए और प्रसूता का इलाज सरकारी खर्च पर हो। परिजनों ने कहा कि अगर समय पर सही इलाज मिलता तो नवजात की जान बच सकती थी। कप्तानगंज थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से पूछताछ शुरू कर दी है। मेडिकल जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जिला प्रशासन ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और अस्पताल की जांच के आदेश दिए हैं। यदि लापरवाही साबित होती है तो अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सैनी कोतवाली क्षेत्र में कच्चा तेल लदा टैंकर पलटा, भीषण आग से जलकर खाक

टीवी भारतवर्ष कौसांबी

सैनी कोतवाली क्षेत्र के लोहंदा मोड़ के पास बुधवार को कच्चा तेल लदा टैंकर अनियंत्रित होकर 11 हजार वोल्ट के बिजली पोल से टकराकर पलट गया। टक्कर के तुरंत बाद टैंकर में आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और पूरी तरह जलकर खाक हो गया। टैंकर दिल्ली से कोलकाता कच्चा तेल लोड कर जा रहा था। जैसे ही यह नेशनल हाईवे पर लोहंदा मोड़ के समीप पहुंचा, अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया और उसमें आग लग गई। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शी राहगीर योगेंद्र ने बताया कि टैंकर चालक तेज रफ्तार में उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर आगे बढ़ा, थोड़ी दूरी पर जाकर टैंकर बिजली पोल से टकराकर पलट गया। उन्होंने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर चालक और परिचालक को टैंकर से बाहर निकाला। साथ ही टैंकर में रखे सिलेंडर और अन्य सामान भी सुरक्षित निकाल लिए गए।

सूचना मिलने पर सैनी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मंझनपुर और सिराथू से भी फायर गाड़ियां बुलाई गईं। फायर कर्मियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया। इस हादसे में चालक और परिचालक घायल हो गए और उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया।

हादसे के कारण कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आग बुझने के बाद पुलिस ने यातायात सुचारू कराया। सैनी कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार और वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है।

बलिया में 2026 बोर्ड परीक्षाओं पर कड़ा पहरा, जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम का अचानक किया निरीक्षण

टीवी भारतवर्ष बलिया

बलिया में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को नकलरहित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि यदि किसी परीक्षा केंद्र पर संदिग्ध गतिविधि या अनुशासनहीनता दिखाई देती है, तो तुरंत संबंधित प्रधानाचार्य को सूचित कर सुधार कराया जाए। सभी केंद्रों पर परीक्षा समय पर शुरू हो और कोई विलंब न हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क है। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में बने कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां कंप्यूटर और बड़ी स्क्रीन के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी परीक्षा कक्षों और स्टैटिक मजिस्ट्रेट कक्षों की निगरानी सुनिश्चित की जाए और किसी भी अनियमितता को तुरंत पकड़ा जाए। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम में स्पीकर और लैंडलाइन कनेक्शन की व्यवस्था का जायजा लिया, ताकि किसी भी परीक्षा केंद्र से तुरंत संवाद स्थापित किया जा सके। इसके बाद उन्होंने कुंवर सिंह इंटर कॉलेज स्थित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर सीसीटीवी पर लाइव निगरानी की व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान प्रशासन की सतर्कता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हुई।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी केंद्रों पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी स्तर पर अनियमितता की संभावना न रहे। प्रशासन की कड़ी निगरानी और सतर्कता के चलते जिले में बोर्ड परीक्षाएं सकुशल और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो रही हैं। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इस तरह बलिया में जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर प्रभावी निगरानी और सतर्कता के माध्यम से छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का कार्य किया है।